

लोकायुक्त

प्रलिस के लयि:

लोकायुक्त, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF), लोकपाल, प्रशासनकि सुधार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम, 2013

मेन्स के लयि:

भारत में लोकायुक्त से संबंधति मुददे

चर्चा में क्यों?

[केरल लोकायुक्त](#) ने [मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष \(Chief Minister's Distress Relief Fund- CMDRF\)](#) में कथति भाई-भतीजावाद और वसिंगतयिों से संबंधति एक मामले को जाँच हेतु तीन सदस्यीय पूरण न्यायपीठ को सौंप दयाि है ।

लोकायुक्त:

परचिय:

- लोकायुक्त भारतीय संसदीय [ओमबुडसमैन](#) है, जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नयुक्त कया जाता है और उसके लयि काम करता है ।
- यह एक भ्रष्टाचार वरिधी व्यवस्था है । कसिी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के वरिद्ध शकियतों, आरोपों की जाँच करना है ।

उत्पत्ति:

- लोकायुक्त व्यवस्था की उत्पत्ति स्कॅडनिवयाई देशों में हुई थी ।
- भारत में [प्रशासनकि सुधार आयोग](#) (1966-70) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सफिराशि की थी ।
- [वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम](#) पारति होने से पहले भारत के कई राज्यों ने 'लोकायुक्त' संस्थान बनाने के लयि कानून पारति कयि ।
 - महाराष्ट्र पहला राज्य था जसिने वर्ष 1971 में लोकायुक्त नकिय स्थापति कया था ।

नयुक्ति:

- लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नयुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है । नयुक्ति करते समय अधकिंश राज्यों में राज्यपाल (a) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और (b) राज्य वधानसभा में वपिक्ष के नेता से परामर्श करता है ।

कार्यकाल:

- अधकिंश राज्यों में लोकायुक्त के लयि नरिधारति अवधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होती है । वह दूसरे कार्यकाल के लयि पुनरनयुक्ति का पात्र नहीं है ।

लोकायुक्त से संबंधति मुददे:

- कोई स्पष्ट कानून नहीं:
 - लोकपाल और लोकायुक्त अधनियम 2013 में लोकायुक्त हेतु केवल एक धारा है, जो अनवार्य करती है किराज्यों को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त अधनियम पारति करना होगा तथा उसकी संरचना, शक्तयिों या अन्य वशिषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।
 - वास्तव में राज्यों को इस बात की पूरण स्वायत्तता है किर उनके अपने लोकायुक्तों की नयुक्ति कसि प्रकार की जाती है, वे कसि प्रकार कार्य करते हैं और वे कनि परस्थितयिों में सेवा करते हैं ।
- समाधान में वलिंब:
 - लोकायुक्त द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतयिों में से एक जाँच और शकियतों के समाधान में देरी है ।
 - लोकायुक्त वतितपोषण और बुनयादी ढाँचे के लयि भी राज्य सरकार पर नरिभर रहता है, जसिसे हस्तक्षेप और स्वतंत्रता की कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

आगे की राह

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को मज़बूत करना:** लोकायुक्त को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने हेतु लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये, जैसे कभिख्यमन्त्री एवं न्यायपालिका सहित सभी लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच तथा मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करना।
- **पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की न्युक्ति:** देश भर में लोकायुक्त कार्यालयों को पर्याप्त रूप से कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता है जिससे वे अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू करा सकें।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि:** लोकायुक्त को अपने कामकाज़ में अधिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता बनाई रखनी चाहिये। उसे नियमि रूप से अपनी गतविधियों, जाँच एवं परणामों पर रपिोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/lokayukta-6>

